आज़ादी का अमृत महोत्सव

पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

पृष्ठभूमि

- दिशा योजना के तहत, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है।
- यह एक बहु-हितधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है जो कानूनी अधिकारों, अधिकारों और प्रासंगिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता के लिए कमजोर वर्गों को सक्षम करने के लिए नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत पद्धति को एकीकृत कर रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
- विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना
- मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग
- प्रभावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना
- समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन

भागीदार एजेंसियां

1. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली**
   राष्ट्रीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
2. **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलूरू, कर्नाटक**
   "डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और आकलन"
3. **राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश**
   "डिजिटल विधिक साक्षरता-डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण –ई–न्यायगंगा"।
4. **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नई दिल्ली**
   "उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करना" (अधिकारों का ज्ञान प्रगति की पहचान)।
5. **अरुणाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश**
   "औपचारिक न्याय प्रदायगी प्रणाली पर गांव बुढा और गांव बुढियों की क्षमता निर्माण द्वारा "पारंपरिक ग्राम न्याय परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की प्रथागत के बीच तालमेल"।
6. **सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू), गंगटोक, सिक्किम**
   "कर्मचारियोंए छात्रों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम, 2005 मानव तस्करी रोध" पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।
7. **मनोचिकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), इम्फाल ईस्ट, मणिपुर**
   "प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करके "बाल यौन शोषण के खिलाफ मीडियाकर्मियों, छात्रों, हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
8. **सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सीकोडेकॉन), जयपुर, राजस्थान**
   "राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना"।
9. **शैडो एडवरटाइजिंग एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा**
   ओडिशा राज्य में "अभिनव विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम"।
10. **यशवंतराव चव्हाण ग्राम विकास और प्रशासन लोक अकादमी (यशदा), पुणे, महाराष्ट्र**
    महाराष्ट्र की विन्हित ग्राम पंचायतों में "विधिद्रूत को बढ़ावा देना"।
11. **विधि अनुसंधान संस्थान (ईएलआरआई), गुवाहाटी, असम**
    "भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत प्रथाओं का दस्तावेजीकरण"।
12. **बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, बिहार**
    ग्रामीण बिहार में विन्हित किए गए "विधि मित्रों को बढ़ावा देना"।
13. **अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर, कर्नाटक**
    (सैटकॉम) प्रौद्योगिकी के माध्यम से "पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों का विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
14. **मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय**
    सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से न्याय तक पहुंच परियोजना।
15. **इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली**
    इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा अमलीकृत "पैरालीगल प्रैक्टिस मजबूतीकरण परियोजना"।

अंतर-मंत्रालयी अभिसरण

पंचायती राज
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

- 4 लघु फिल्में विकसित की गई हैं। इन लघु फिल्मों का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भी प्रसार किया जा रहा है।

Ministry of Education
Government of India
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई कानूनी साक्षरता सामग्री शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए वेब पोर्टल दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) पर अपलोड की गई है।

कानूनी जानकारी के लिए सरलीकृत डिजिटल समाग्री

इत्ती सी हसी	जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया	लाखों तारे आसमान में	हम है रही प्यार के
https://youtu.be/Pu6-jembih0	https://youtu.be/mHKUHL0npKI	https://youtu.be/y55gzl7I8Qs	https://youtu.be/HI0RoBETkwo

सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर वेबिनार

न्याय विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय-स्तर के सामाजिक कानूनी मुद्दों पर कानूनी जागरूकता वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अब तक न्याय विभाग ने बीस वेबिनार आयोजित किए हैं। इन बीस राष्ट्रीय-स्तरीय वेबिनारों के माध्यम से न्याय विभाग 4.62 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच चुका है।

22 सितंबर, 2021 को 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' 2005 पर आयोजित वेबिनार, 48,299+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

14 नवंबर, 2021 को 'बाल अधिकारों पर आयोजित वेबिनार' 17,644+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

26 नवंबर, 2021 को 'मौलिक कर्तव्य' विषय पर आयोजित वेबिनार, 24,082+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

7 जनवरी, 2022 को 'गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994' पर आयोजित वेबिनार, 15,080+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

18 फरवरी, 2022 को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' पर आयोजित वेबिनार, 19,158+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

8 मार्च, 2022 को 'भारत में लैंगिक न्याय' पर आयोजित वेबिनार, 35,332+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

25 अप्रैल, 2022 को 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 20,207+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

27 मई, 2022 को 'देखभाल एवं संरक्षण की जरुरत वाले बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 24,715+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

29 जून, 2022 को 'मानव तस्करी' पर आयोजित वेबिनार 30,627+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

31 अगस्त, 2022 को 'वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार' पर आयोजित वेबिनार, इसे 13,255+ लाभार्थियों से संपर्क किया गया ।

28 अक्टूबर, 2022 को **'भारत में साइबर अपराध'** पर आयोजित वेबिनार **30,442+** लाभार्थियों तक पहुंचा ।

25 नवंबर, **2022** को **'संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों'** पर आयोजित वेबिनार **37,481+** लोगों तक पहुंचा ।

27 दिसंबर, **2022** को **'भारत में विकलांग व्यक्तियों'** के अधिकार पर आयोजित वेबिनार **16,612+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

30 जनवरी, **2023** को **'भारत में विचाराधीन कैदियों'** के अधिकार पर आयोजित वेबिनार **17,960+** कार्यकर्ताओं तक पहुंचा ।

6 मार्च, **2023** को **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों का संरक्षण'** पर आयोजित वेबिनार **29,851+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

28 मार्च, **2023** को **'उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण'** पर आयोजित वेबिनार **21,143+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

12 जून, **2023** को **'भारत में बाल श्रम'** पर आयोजित वेबिनार **25,133+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

18 जुलाई, **2023** को **'एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास'** पर आयोजित वेबिनार **15,127+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

29 सितम्बर, **2023** को **'श्रम कानून'** पर आयोजित वेबिनार **2153+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

31 अक्टूबर, **2023** को **'बाल यौन शोषण'** पर आयोजित वेबिनार **33,318+** प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

डिजिटल लाइब्रेरी

हमारे उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर कानूनी ज्ञान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्कैन करें

न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

2024

झलकियाँ राज्य स्तरीय कानूनी जागरूकता गतिविधियाँ

सोशल मीडिया से डिजिटल कानूनी साक्षरता के लिए संपर्क करे **CEERA - NLSIU** का **QR** कोड स्कैन करें

समाचार में पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ

Awareness drive on consumer rights & sexual harassment

STATESMAN NEWS SERVICE
KORAPUT, 11 JANUARY

With an aim to create awareness on consumer's rights and sexual harassment of women at workplace, Department of Justice, commenced an Information, Education & Communication (IEC) awareness campaign on "Consumer Protection Act, 2019" and "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" to be held in various district of Odisha. As part of the ...

In Koraput and it will run in other 8 districts of Odisha including Rayagada, Gajapati, Ganjam, Khurda, Cuttack, Puri, Jagatsinghpur and Kendrapada ...

Union Justice Dept holds awareness campaign on Consumer Protection Act

PBD BUREAU
KORAPUT, JAN 11

WITH an aim to create awareness on consumer's rights, and sexual harassment of women at workplace, Union Justice Department commenced an Information, Education & Communication (IEC) ...

organized in Koraput and this will run Rayagada, Gajapati, Ganjam, Khurda, Cuttack, Jagatsinghpur, Puri, Kendrapada districts of the state.

In several remote and interior villages of Odisha, peoples were least or partially aware about their basic rights. Through this IEC awareness campaign peo-...

एनएलआईयू के 'ई-न्यायगंगा' से जानें क्या है सूचना का अधिकार

भारत का कोई भी नागरिक मांग सकता है 'सार्वजनिक प्राधिकरण' से जानकारी

जानें अपने अधिकार

आम नागरिक कैसे मांग सकते हैं जानकारी

ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದರ ಪಾಟೀಲ ಇ.ಓ.

ସମ୍ବାଦ
15 Jan 2023 - Page 10

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା

ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଇଇସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

सभ्य समाज में किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं, जागरूकता ही उपाय

IEC awareness campaign on sexual harassment at workplace

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 23 JANUARY

With an aim to create awareness on consumer's rights and sexual harassment of women at workplace, the Department of Justice organized an IEC Awareness Campaign on "Consumer Protection Act, 2019" and "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". As part of the campaign, ... was organized ... of Cuttack ...

SEXUAL HARASSMENT: NOT IN MY WORKPLACE

Kendra- CSC; Radheshyam Behera, Senior Advocate, Orissa High Court; Pranaya Swain, Advocate, Visakha Bardhan, Law Student from Madhusudan Law University and women representatives from various SHGs participated ...

sory education through the IEC awareness campaign. Also women of various area got aware relating to their rights and safety from violence."

Sensitive topics & issues like Rights of the Children to Free & Compulsory Education, Protection of Women from Domestic Violence Act, Women Rights, and Prevention of Children from Sexual Offence Act (POCSO) were all discussed and the audiences were informed about their rights.

विधिक साक्षरता जागरूकता पर जिला स्तरीय बैठक

■ निर्भीक राजस्थान
करौली। भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे हैं विधिक साक्षरता एवं ...

Workshop held on legal literacy and awareness

The Centre for Environmental Law & Pro Bono Club, and Legal Aid Centre, **Maharashtra National Law University** (MNLU) Nagpur, organized one-day master trainer workshop on 'Legal literacy and legal awareness' in association with the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, and the **Centre for Environmental Law, Education, Research and Advocacy** (CEERA), NLSIU, Bengaluru, recently. **Jaydip Govardhan Pa...** secretary, District Legal Services Authority, Nagpur, professor **Himanshu Pandey**, MNLU, **Ashish J Dixit**, registrar, MNLU, and **Veena Roshan Jo...** convenor and centre-in-charge, Centre for Environmental L... were present. Pandey spoke on significance of ... awareness in the paradigm of social ...

Free Psycho-Social counselling

IMPHAL, Mar 20

The Department of Psychiatry, JNIMS under the aegis of the Department of Justice, Ministry of Law & Justice, Government of India is providing free specialized Psycho-Social counselling to individuals, family and caregivers of Child Sexual Abuse from 10 am to 12.30 pm at OPD, 1st floor, Department of Psychiatry, JNIMS.

A statement by the Project Coordinator, Department of Psychiatry, JNIMS also ...

ಕೋಲಾರ ವಾಹಿನಿ KOLARA VAHINI

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ; ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಿ

कायद्यावर आधारित शिबीर संपन्न

The Legal Aid Clinic of Kirit P Mehta School of Law NMIMS recently organised a workshop in association with the Ministry of Law and Justice & CEERA-NLSIU

The Legal Aid Clinic of Kirit P Mehta School of Law NMIMS recently organised a workshop in association with the Ministry of Law and Justice & CEERA-NLSIU under the aegis of the Department of Justice. The Ministry of Law ... working on Project PAN India, ... Legal Literacy and Legal Awareness Programme that aims to empower ... disadvantaged sections of society and demand justice services.

ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା

ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ